

शिक्षा का जनजातीय समाज के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव

डॉ० सुनीता बघेल

एम० पी० सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

परम्परागत जनजातीय परिवार का शैक्षणिक स्तर अत्यन्त निम्न रहा है। आधुनिक काल में शिक्षा प्रसार की व्यापक प्रक्रिया और जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है जिससे जनजातीय समुदाय प्रभावित हो रहा है। जनजातीय समुदायों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए उनके राजनीतिक जीवन पर शिक्षा का प्रभाव की जानकारी उत्तरदाताओं से ली गई।

शब्द कुंजी : बैगा जनजाति, ग्राम सभा, 73वें संवैधानिक संशोधन, शिक्षा का जनजातीय समाज के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव।

प्रस्तावना

परम्परागत जनजातीय परिवार का शैक्षणिक स्तर अत्यन्त निम्न रहा है। आधुनिक काल में शिक्षा प्रसार की व्यापक प्रक्रिया और जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है जिससे जनजातीय समुदाय प्रभावित हो रहा है। जनजातीय समुदायों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए उनके राजनीतिक जीवन पर शिक्षा का प्रभाव की जानकारी उत्तरदाताओं से ली गई। प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी क्रमांक 5.35 में प्रदर्शित किया गया है।

भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाएँ हैं। इन्हीं समुदायों में से एक है जनजातीय समुदाय, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है। इस आदिवासी समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग नामों की संज्ञा दी है। मार्टिन एवं रिजले ने इन्हें 'आदिवासी' हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियाँ' सर वेन्स ने इन्हें 'पर्वतीय आदिम जातियाँ' या वन्य जातियाँ घुरिये ने इन्हें 'पिछड़े हुए हिन्दु' तथा वनों में रहने के कारण गाँधीजी ने इन्हें 'गिरिजन' के नाम से पुकारा है। भारतीय संविधान में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से सूचीबद्ध किया गया है (पालोत, आर. सी. 1987: 1)।

यह समुदाय प्रारम्भ से ही जंगलों, पहाड़ों एवं दूर-दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, अशिक्षा तथा शोषण का शिकार, कृषि, उद्योग-धंधों आदि से अनभिज्ञ रहा है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है। यह समुदाय अपने सीमित संसाधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सका है और आज भी 21वीं शताब्दी की विज्ञानवादी सभ्यता की पहुँच इनसे काफी दूर है (गुप्ता, 2003: 1-4)।

अध्ययन हेतु समग्र के रूप में मध्यप्रदेश राज्य के बालाघाट जिले का चयन किया गया है। बालाघाट जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है जिसमें तीन विकासखण्ड बैहर, बिरसा, एवं परसवाडा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं अध्ययन हेतु सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य दो विकासखण्ड, बैहर तथा बिरसा को चयनित किया गया है। यहाँ जनजातीय विकास के लिए

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अनेक कार्य सरकारी एवं गैर-सरकारी तौर पर किया जा रहा है जिससे जनजातीय समाज में आये परिवर्तनों का अध्ययन, की महती आवश्यकता है। इन चयनित दो विकासखण्डों से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पांच-पांच ग्राम चयनित किये गये। इस प्रकार दो विकासखण्डों में से कुल 10 ग्राम को अध्ययन हेतु चुना गया। प्रत्येक ग्राम से 18 जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं 6 गैर-जनजातीय ग्राम सभा सदस्यों को यादृच्छिक आधार पर चयनित किया गया। इस प्रकार 10 ग्रामों से 180 जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं 60 गैर-जनजातीय ग्रामसभा सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अतः निदर्शन का कुल आकार 240 है।

अध्ययन में विषय से सम्बंधित द्वितीयक तथ्यों से भी संकलन किया गया। इस हेतु विषय से सम्बंधित पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, पुस्तकें, जर्नल्स, समाचार-पत्र, अध्यादेश, अधिनियम, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रकाशित/अप्रकाशित अभिलेखों, रिपोर्टों, विवरणिकाओं आदि से तथ्य संग्रहीत किए गये।

अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। बालाघाट जिला 21°09 से 22°24 उत्तरी अक्षांश तथा 79°31 से 81°03 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बालाघाट जिले की सीमा दो राज्यों को छूती है। दक्षिण में यह महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा एवं नागपुर जिले से मिलती है जबकि पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) जिले से मिलती है। पश्चिम में सिवनी जिला तथा उत्तर में मंडला जिला इसकी सीमाओं को छूता है। बालाघाट जिले का कुल क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बालाघाट जिला 8 तहसीलों, 10 विकासखण्डों एवं 629 ग्राम पंचायतों में विभाजित है।

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 17,01,698 है। जिसमें जनजातियों की जनसंख्या 3,83,026 है जो कुल जनसंख्या का 22.5 प्रतिशत है। बालाघाट जिले की साक्षरता 77.1 प्रतिशत है जिसमें पुरुष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 85.4 व 69.0 है। जबकि जिले में जनजातियों की साक्षरता 67 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष 37 प्रतिशत एवं महिला 31 प्रतिशत है।

सारणी 1: शिक्षा के साधनों ने राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया?

क्र. सं.	शिक्षा के साधनों ने आप के राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है?	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	आपकी राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है।	161 (89.4)	47 (78.3)
2	राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है।	162 (90.0)	47 (78.3)
3	आपके मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है।	165 (91.6)	46 (76.6)
4	आपकी दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है।	160 (88.8)	45 (75.5)
5	मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है।	163 (90.5)	43 (71.6)
6	राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए हैं।	161 (89.4)	41 (68.3)

सारणी क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि 89.4 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं का समान रूप से मानना है कि शिक्षा के साधनों से राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है एवं राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए हैं। 90.0 प्रतिशत का मानना है कि शिक्षा के साधनों से राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव जरूर आया साथ इन प्रवृत्ति में वृद्धि भी हुई है, जबकि 91.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार शिक्षा के साधनों से मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है अतः जनजाति युवा पीढ़ी में ये परिवर्तन अधिक देखने को मिला है। 88.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा के साधनों से दलीय निष्ठा में भी परिवर्तन हुआ है, 90.5 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के साधनों से मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया जिससे हम लोगों को फायदा हुआ है, तथा गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं में 78.3 प्रतिशत का समान रूप से मानना है कि शिक्षा के साधनों से राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है, एवं राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव जरूर आया साथ इन प्रवृत्ति में वृद्धि भी हुई है, जबकि 76.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार शिक्षा के साधनों से मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है अतः जनजाति युवा पीढ़ी में ये परिवर्तन अधिक देखने को मिला है। 75.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा के साधनों से दलीय निष्ठा में भी परिवर्तन हुआ है, 71.6 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के साधनों से मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया जिससे हम लोगों को फायदा हुआ है, तथा 68.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा के साधनों ने राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि जनजातीय समाज में शिक्षा के साधनों से उनके मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है, मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है एवं राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

परम्परागत जनजातीय परिवार का शैक्षणिक स्तर अत्यन्त निम्न रहा है। आधुनिक काल में शिक्षा प्रसार की व्यापक प्रक्रिया और जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है जिससे जनजातीय समुदाय प्रभावित हो रहा है। जनजातीय समुदायों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए उनके राजनीतिक जीवन पर शिक्षा का प्रभाव की जानकारी उत्तरदाताओं से ली गई। बहुसंख्यक उत्तरदाताओं का मानना है कि जनजातीय समाज में शिक्षा के साधनों से मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है। मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है एवं राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में

बदलाव आया/वृद्धि हुई है। अतः स्पष्ट है कि जनजातीय समाज में शिक्षा के साधनों से उनके मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है, मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है एवं राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है।

सुझाव

जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

- जनजातीय समाज को शिक्षित बनाते हुए, उन्हें योजना के कार्यक्रमों एवं प्रावधानों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस हेतु जनजातीय ग्रामों में जन-शिक्षण के कार्यक्रम, जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अन्य प्रचार के माध्यमों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
- विकास योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए। इस सन्दर्भ में साप्ताहिक/दैनिक बाजारों, हाटों, सड़क के किनारे, चौराहे तथा ग्राम सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग को जोड़ा जाए एवं उन्हें कोई व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता की जाए इससे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन में सुधार भी होगा तथा उनके जीवन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों को शासन द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण भिविर लगाए जाए।
- जनजातीय ग्राम में ऐसा अभिकरण (कार्यालय) स्थापित किया जाए जिससे ग्रामवासियों को रोजमर्रा की सूचनाएँ प्राप्त हो एवं समस्याओं का निदान किया जा सके और उन्हें सूचना के अधिकारों के प्रति जाग्रत किया जाए।
- जनजातीय क्षेत्रों में टेलीविजन पर अधिक से अधिक समाचार चैनलों का प्रसारण किया जाए जिससे जनजातीय समुदाय में राजनीतिक सजगता को बढ़ावा मिले।
- गैर-सरकारी संगठनों को कार्यों के चयन तथा क्रियान्वयन में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाते हुए अधिकांश लोगों की सहमति से कार्य करना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय की भागीदारी बढ़ सके।
- शिक्षण संस्थाएँ राजनीतिक समाजीकरण में सही भूमिका निभा सके इसलिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पहुँच उन तक हो जिससे राजनीतिक समाजीकरण के आधारभूत अभिकरणों के रूप में सही भूमिका निभा सके।
- जन-संचार के माध्यम अत्यधिक सीधे रास्ते से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए की संचार माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण

रखकर इनकी सहायता से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। संक्षेप में जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, संचार के साधन, राजनीतिक दल, गैर-सरकारी संगठन, सरकार की अन्य योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तथापि जनजातीय क्षेत्रों में इन साधनों का प्रभाव व जन-सहभागिता में कमी एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यमान रहा है। अतः यह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर जनजातीय समुदाय को उचित अवसर प्राप्त हो तभी इस समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती है।

संदर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 178-186।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधान: एक परिचय, लेक्सिस नेक्सस, गुडगाँव हरियाणा पृ. 108-115।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ. 1-4।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मैकलेण्ड, जे एम (1967): मासा मीडिया एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पेपर प्रेसेन्टेड एट द एसोसिएशन फॉर एज्युकेशन इन जर्नलिज्म, बोल्टर पृ. 78-80।
8. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशन्स उदयपुर, पृ. 54-55।
9. मिश्रा, राजीव (2008): वालेन्टरी सेक्टर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 50-60।
10. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धांत, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3-5 पृ. 1-9।
11. पालोत, आर सी (1987): राजस्थान की वनविहारी जनजातियाँ, नीलकमल ब्रदर्स, डूंगरपुर पृ. 1।
12. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
13. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. 85-86।
14. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6-14।
15. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6-16।
16. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आशीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था: विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 34।
17. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 100-112।
18. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति पृ. 8-13।
19. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियाँ,

- हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 200।
20. राकेश, भट्ट (1995): जनजातीय उद्यमिता का विकास, हिमांशु पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 8-13।
 21. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 2-4।
 22. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेंट इन इंडिया: ए क्रिटिकल अप्राजल, क्राउन पब्लिकेशन्स राची पृ. 193।
 23. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकास: मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 7-16।